न्यायमूर्ती टी. एच. बी. चलपति के समक्ष

चमेला राम,-अपीलार्थी

बनाम

बलवंत सिंह और अन्य-उत्तरदाता

***1997* का आर. एस. ए. सं. 1112**

21 जनवरी, 1999

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908-धारा 153-एक मृत व्यक्ति के खिलाफ दायर मुकदमा-कानूनी प्रतिनिधियों को रिकॉर्ड पर लाया गया-क्या मुकदमा अमान्य है।

अभिनिर्धारित किया गया कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह सच है कि किसी मृत व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता है। मृत व्यक्ति के खिलाफ दायर किया गया ऐसा मुकदमा अमान्य है। लेकिन प्रतिवादी की मृत्यु के बारे में पता चलने पर वादी धारा 153 *सिविल प्रक्रिया संहिता* के प्रावधानों के तहत याचिका में संशोधन की मांग कर सकता है और मृतक के कानूनी प्रतिनिधि को मुकदमे में पक्षकार के रूप में शामिल कर सकता है यदि संशोधन के लिए आवेदन करते समय मुकदमा वर्जित नहीं है।

(पैरा 7)

विशिष्ट राहत अधिनियम, 1877-विशिष्ट निष्पादन के लिए मुकदमा-बिक्री के निष्पादन के लिए निर्धारित तिथि में परिवर्तन-का प्रभाव।

यह अभिनिर्धारित किया गया कि बिक्री समझौते पर अनुमोदन की जांच पर, जिसे 'ए' चिह्न के रूप में चिह्नित किया गया है, मुझे यह अभिनिर्धारित करने में कोई संदेह नहीं है कि 15 नवंबर, 1987 की तारीख को 15 नवंबर, 1988 के रूप में बदल दिया गया है। वादी द्वारा इस परिवर्तन की व्याख्या नहीं की गई है। भारत में अंग्रेजी कानून में पालन किया जाने वाला सामान्य नियम यह है कि साक्ष्य में प्रस्तुत दस्तावेज़ पर अभिरक्षा या नियंत्रण रखने वाले पक्ष को परिवर्तन की व्याख्या करनी चाहिए। जब लिखित कथन में यह स्पष्ट रूप से कहा जाता है कि तारीख में बदलाव किया गया है और जब इसके उत्पादन पर दस्तावेज़ में बदलाव किया गया प्रतीत होता है, तो यह सामान्य नियम है कि साक्ष्य में दस्तावेज़ की पेशकश करने वाले पक्ष को इसकी उपस्थिति की व्याख्या करनी चाहिए क्योंकि उपकरण में प्रत्येक परिवर्तन इसे संदिग्ध बनाता है। यह केवल उचित है कि दस्तावेज़ के तहत दावा करने वाले पक्ष को संदेह को दूर करना चाहिए। इस प्रकार, यदि दस्तावेज़ भौतिक रूप से परिवर्तित प्रतीत होता है, तो कानून स्वाभाविक रूप से वादी पर परिवर्तन की व्याख्या करने और यह दिखाने के लिए भारी बोझ डालता है कि यह कब किया गया था। आम तौर पर, जो पक्ष उस दस्तावेज को प्रस्तुत करता है जो उसके मामले का एक अनिवार्य हिस्सा है, यदि ऐसा दस्तावेज़ मे बदलाव किए जाते है तो और बदले जाने का कोई सपष्टीकरण नहीं दिया जाता तो संदिग्ध रंग के कारण, ऐसे दस्तावेज़ विफल होना चाहिए।

(पैरा 16)

अपीलार्थी की ओर से *अधिवक्ता ए. के. मित्तल।*

महावीर संधू, अधिवक्ता, *उत्तरदाता संख्या 1,4 और 6 के लिए।*

निर्णय

टी. एच. बी. चलपति, न्यायमूर्ति

(1) वादी द्वारा यह अपील 13 जनवरी, 1997 को 1994 की सिविल अपील संख्या 54 में जगाधरी में विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, यमुनानगर के डिक्री और फैसले के खिलाफ निर्देशित की गई है।

(2) वादी ने विक्रय करने के करार कि विनिर्दिष्ट पालन के लिए मुकदमा दायर किया, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसे प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा 29 नवंबर, 1986 को 35,000 रुपयों के प्रतिफल के साथ निष्पादित किया गया था और उसी दिन 5000 रुपये अग्रिम जमा राशि प्राप्त की। प्रतिफल कि बकाया राशि बिक्री विलेख के पंजीकरण के समय उप-पंजीयक के समक्ष भुगतान करने पर सहमति व्यक्त की गई थी, जिसे 15 जून, 1987 को निष्पादित करने पर सहमति व्यक्त की गई थी, लेकिन प्रतिवादी सहमति के अनुसार विक्रय विलेख को निष्पादित करने में विफल रहा। इसलिए, वादी ने विक्रय करने के करार कि विनिर्दिष्ट पालन के लिए मुकदमा दायर किया।

(3) यह मुकदमा मूल रूप से गुलाब सिंह के खिलाफ दायर किया गया था। यह पता चला कि प्रतिवादी गुलाब सिंह की मुकदमा दायर करने से पहले ही मृत्यु हो गई थी। इसके बाद, वादी ने मुकदमे में प्रतिवादी संख्या 2 से 6 के रूप में प्रतिवादी के कानूनी प्रतिनिधियों को शामिल किया।

(4) प्रतिवादी 2 से 6 ने प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा विक्रय करने के करार के निष्पादन को स्वीकार किया। लेकिन उन्होंने तर्क दिया कि वादी अपने अनुबंध के अपने हिस्से का पालन करने के लिए तैयार और इच्छुक नहीं था और अनुबंध के पालन के लिए समय बढ़ाने के समर्थन में भौतिक परिवर्तन है और वादी की विफलता के कारण, बकाया धन जब्त कर लिया गया है। मृत व्यक्ति के खिलाफ दायर किया जा रहा मुकदमा सुनवाई योग्य नहीं है।

(5) निचली अदालत ने उचित मुद्दे तैयार करने और रिकॉर्ड पर सामग्री पर विचार करने के बाद मुकदमे को खारिज कर दिया। वादी द्वारा दायर अपील भी असफल रही। इसलिए यह दूसरी अपील डाली गई है।

(6) प्रतिवादी-प्रतिवादी के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि एक मृत व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दायर किया गया है

जो कानून की नजर में कुछ नहीं माना जाता। आदेश 22 *सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908* के प्रावधानों के तहत कानूनी प्रतिनिधियों को रिकॉर्ड पर नहीं लाया जा सकता है।

(7) इसमें कोई संदेह नहीं है कि किसी मृत व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता

है। मृत व्यक्ति के खिलाफ दायर किया गया ऐसा मुकदमा अमान्य है। लेकिन प्रतिवादी की मृत्यु के बारे में पता चलने पर वादी धारा 153 *सिविल प्रक्रिया संहिता* के प्रावधानों के तहत वादपत्र में संशोधन की मांग कर सकता है और मृतक के कानूनी प्रतिनिधियों को मुकदमे में पक्षकार के रूप में शामिल कर सकता है यदि संशोधन के लिए आवेदन करते समय मुकदमा वर्जित नहीं है।

(8) गोपालकृष्ण *बनाम* आदिवी *लक्ष्मण राव*[1] मद्रास उच्च न्यायालय की एक पूर्ण पीठ ने कहा कि यदि किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ अपील प्रस्तुत की जाती है जो प्रस्तुत करने की तारीख पर मर चुका है, तो न्यायालय *सिविल प्रक्रिया संहिता* की धारा 153 के तहत कारण शीर्षक में संशोधन की अनुमति दे सकता है या संशोधन और प्रतिनिधित्व के लिए अपील के ज्ञापन को वापस कर सकता है।

(9) के इस्माइल बनाम पलायत कोप्पडेकबल पाव *पावा अम्मा* और *अन्य*[2] *में भी यही दृष्टिकोण लिया* गया था।

(10) छतर *प्रसाद बनाम* बैजिनाथ *प्रसाद*[3] *में*, यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यद्यपि एक मृत व्यक्ति के खिलाफ अपील एक अपील नहीं है, लेकिन इसे *सिविल प्रक्रिया संहिता* की धारा 153 के साथ पठित आदेश 1 नियम 10 के प्रावधानों के तहत संशोधित करने की अनुमति दी जा सकती है।

(11) लाहौर उच्च न्यायालय ने भी मेहर सिंह बनाम लाभ सिंह[4] *मामले में* यही *दृष्टिकोण अपनाया* है।

(12) इसलिए, मुझे उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील के तर्क में कोई बल नहीं मिलता है क्योंकि इस मामले में उत्तरदाता के कानूनी प्रतिनिधियों को पक्षकारों के रूप में शामिल किया गया है।

(13) 29 नवंबर, 1986 के बिक्री समझौते के निष्पादन को प्रतिवादियों द्वारा स्वीकार किया गया था, लेकिन उन्होंने इस बात से इनकार किया कि बिक्री विलेख के निष्पादन का समय 15 नवंबर, 1988 तक बढ़ा दिया गया था और लेनदेन को पूरा करने के लिए समय 15 जून, 1987 तक निर्धारित किया गया था। वादी के अनुसार, विक्रेता गुलाब सिंह ने 15 जून, 1987 को समय बढ़ाकर 15 नवंबर, 1988 कर दिया, लेकिन प्रतिवादियों के अनुसार, बिक्री के समझौते पर अनुमोदन को महत्वपूर्ण रूप से बदल दिया गया था और समय मूल रूप से 15 नवंबर, 1987 तक बढ़ाया गया था, लेकिन इसे 15 नवंबर, 1988 कर दिया गया था। विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने पाया कि तिथि में भौतिक परिवर्तन किया गया है। मैंने दस्तावेज़ भी देखा था। बिक्री के समझौते पर अनुमोदन की बारीकी से जांच करने पर, यह स्पष्ट है कि वर्ष का उल्लेख मूल रूप से 1987 के रूप में किया गया था, लेकिन इसे 1988 के रूप में बनाया गया था। 1987 से 1988 के वर्ष में हुआ परिवर्तन नंगी आँखों से भी स्पष्ट नजर आता है। इसलिए, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि 15 नवंबर, 1987 की तारीख को 15 नवंबर, 1988 के रूप में बदल दिया गया था। इस प्रकार,

[1] A.I.R. 1925 Mad. 1210.
[2] A.I.R. 1955 Mad. 644.
[3] A.I.R. 1930 All. 131.
[4] A.I.R. 1932 Lah. 305.

लेन-देन को पूरा करने के लिए सहमत अवधि को बदल दिया गया। यह महत्वपूर्ण परिवर्तन के बराबर है।

(14) यह तय करने क लिए कि परिवर्तन महत्वपूर्ण था, इस विषय मे यह विचार करना आवश्यक है कि क्या परिवर्तन ने किसी भी पक्ष के दायित्व को प्रभावित किया है। इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि 15 नवंबर, 1987 से 15 नवंबर, 1988 तक दस्तावेज़ की तारीख के परिवर्तन ने प्रतिवादी के दायित्व को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया क्योंकि इसने उस समय को बढ़ा दिया जिसके भीतर वादी मुकदमा करने का हकदार था। जब यह एक महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है, तो यह दस्तावेज़ को शून्य कर देता है। इस संदर्भ में, नाथू लाई और अन्य बनाम माउंट गोमती कुर *और अन्य*[5] *में* प्रिवी *काउंसिल के निर्णय का उल्लेख* करना उपयोगी है, जिसमें इसे निम्नानुसार देखा गया हैः—

> "किसी विलेख में उसके निष्पादन के बाद, किसी भी पक्ष द्वारा या उसकी सहमति से किए गए महत्वपूर्ण परिवर्तनों के प्रभाव से संबंधित नियम, जैसा कि अंग्रेजी न्यायालयों में प्रचलित है, भारतीय मामलों पर लागू होता है और संक्षेप में निम्नानुसार कहा जा सकता हैः
>
> यदि किसी विलेख के भौतिक भाग में उसके निष्पादन के बाद, किसी भी पक्ष या उसके तहत हकदार व्यक्ति की सहमति से या उसके साथ, लेकिन पक्ष या उसके तहत उत्तरदायी पक्षों की सहमति के बिना कोई परिवर्तन (विलोपन, अंतर्वेशन या अन्यथा) किया जाता है, तो विलेख को शून्य कर दिया जाता है। हालाँकि, टालना शुरुआत *से या* किसी भी परिवहन प्रभाव को रद्द करने के लिए नहीं है जो विलेख में पहले ही हो चुका हैः लेकिन केवल इस तरह के परिवर्तन के समय से ही काम करता है और ताकि उस व्यक्ति को जिसने परिवर्तन किया है या अधिकृत किया है और जो उसके अधीन दावा कर रहे हैं, उन्हें किसी भी पक्ष के खिलाफ, जिसके द्वारा परिवर्तन के लिए सहमति नहीं दी गई है, किसी भी पक्ष को लागू करने के लिए विलेख डालने से रोका जा सके। बाध्यता, वाचा या इस प्रकार किए गए या किए गए वादे।
>
> एक महत्वपूर्ण परिवर्तन वह है जो विलेख द्वारा निर्धारित पक्षों के अधिकारों, देनदारियों या कानूनी स्थिति को उसकी मूल स्थिति में बदल देता है या अन्यथा मूल रूप से व्यक्त किए गए साधन के कानूनी प्रभाव को बदल देता है, या निश्चित रूप से कुछ प्रावधान को कम कर देता है जो मूल रूप से अप्रमाणित था और इस तरह से शून्य था, या अन्यथा मूल रूप से किए गए विलेख द्वारा बाध्य पक्ष को पूर्वाग्रहित कर सकता है।
>
> बाध्य पक्ष की सहमति के बिना इस तरह का परिवर्तन करने का प्रभाव ठीक विलेख को रद्द करने के समान है। विलेख से बचना पूर्वव्यापी नहीं है और इसके तहत पारित संपत्ति में किसी भी संपत्ति या हित को संशोधित या पुनर्निर्धारित नहीं करता है। और विलेख को यह साबित करने के लिए साक्ष्य में रखा जा सकता है कि ऐसी संपत्ति या ब्याज इस तरह से पारित किया गया है या इसमें निहित किसी समझौते को लागू करने के

लिए कार्रवाई बनाए रखने के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए है।''

(15) लून करण सेतिया बनाम इबान ई. जॉन[6] मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त *निर्णय को मंजूरी* दी *गई थी। हैल्सबरी* के लॉज़ ऑफ़ इंग्लैंड के चौथे संस्करण के चौथे खंड को पैरा 459 और 460 में उद्धृत करना भी उपयुक्त है जिसमें इसे निम्नानुसार कहा गया हैः—

''जहां कोई लिखत, या यदि कोई स्वीकृति का बिल, सभी उत्तरदायी पक्षों की सहमति के बिना भौतिक रूप से परिवर्तित किया जाता है, तो उस लिखत को सभी पक्षों के संबंध में टाला जाता है, सिवाय किसी ऐसे व्यक्ति के जिसने स्वयं परिवर्तन किया है, अधिकृत किया है या परिवर्तन के लिए सहमति दी है, और जो सामग्री परिवर्तन के बाद लिखत के पक्षकार बन गए हैं।

निम्नलिखित परिवर्तनों को विशेष रूप से महत्वपूरण घोषित किया गया हैः(1) तिथि; (2) देय राशि; (3) भुगतान का समय; (4) भुगतान का स्थान, या भुगतान के स्थान को जोड़ना जहां स्वीकारकर्ता द्वारा उल्लेख किया गया है, स्वीकारकर्ता की सहमति के बिना।" उपरोक्त चर्चा और विक्रय करने के करार के अनुमोदन की जांच पर, जिसे 'ए' चिह्न के रूप में चिह्नित किया गया है, मुझे यह मानने में कोई संदेह नहीं है कि 15 नवंबर, 1987 की तारीख को 15 नवंबर, 1988 के रूप में बदल दिया गया है। वादी द्वारा इस परिवर्तन की व्याख्या नहीं की गई है। भारत में अंग्रेजी कानून में पालन किया जाने वाला सामान्य नियम यह है कि साक्ष्य में प्रस्तुत दस्तावेज़ पर अभिरक्षा या नियंत्रण रखने वाले पक्ष को परिवर्तन की व्याख्या करनी चाहिए। जब प्रतिरक्षा के लिखित कथन में यह स्पष्ट रूप से कहा जाता है कि तिथि में परिवर्तन किया गया है और जब इसके उत्पादन पर दस्तावेज़ में परिवर्तन किया गया प्रतीत होता है, तो यह एक सामान्य नियम है कि साक्ष्य में दस्तावेज़ की पेशकश करने वाले पक्ष को इसके रूप की व्याख्या करनी चाहिए क्योंकि उपकरण में प्रत्येक परिवर्तन इसे संदिग्ध बनाता है। यह केवल उचित है कि दस्तावेज़ के तहत दावा करने वाले पक्ष को संदेह को दूर करना चाहिए। इस प्रकार, यदि साधन महत्वपूर्ण रूप से परिवर्तित प्रतीत होता है, तो कानून स्वाभाविक रूप से वादी पर परिवर्तन की व्याख्या करने और यह दिखाने के लिए भारी बोझ डालता है कि यह कब किया गया था। आम तौर पर, जो पक्ष उस दस्तावेज़ को प्रस्तुत करता है जो उसके मामले का एक आवश्यक हिस्सा है, यदि ऐसा दस्तावेज़ मे बदलाव किए जाते है तो और बदले जाने का कोई सपष्टीकरण नहीं दिया जाता तो संदिग्ध रंग के कारण, ऐसे दस्तावेज़ विफल होगा। वादी केवल उस लेखक के बयान पर भरोसा कर रहा है जिसमें उसने बदलाव किया था। यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं है कि परिवर्तन निष्पादक की उपस्थिति में और उसकी सहमति से किया गया था। इस संबंध में किसी भी स्वीकार्य साक्ष्य के अभाव में, वादी जो विक्रय करने के करार को लागू करना चाहता है, उसे विफल होना चाहिए क्योंकि यह दिखाने की जिम्मेदारी उसके ऊपर थी कि महत्वपूर्ण परिवर्तन या तो पक्षों की सहमति से या पार्टियों के सामान्य इरादे को प्रभावी बनाने के लिए किया गया था। अभिलेख पर पूरे साक्ष्य पर विचार करने और दस्तावेज़ की बारीकी से जांच करने पर, एकमात्र अप्रतिरोध्य

निष्कर्ष यह है कि विक्रय करने के करार के अनुमोदन को भौतिक रूप से बदल दिया गया था ताकि यह प्रतीत हो सके कि तारीख 15 नवंबर, 1988 तक बढ़ा दी गई थी, हालांकि मूल रूप से किए गए अनुमोदन से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि इसे 15 नवंबर, 1987 तक बढ़ाने का इरादा था। वादी का मुकदमा विफल होना चाहिए। जिस दृष्टिकोण को मैं ले रहा हूं, मेरे लिए इस प्रश्न में जाना आवश्यक नहीं है कि क्या वादी अनुबंध के अपने हिस्से का पालन करने के लिए तैयार है और इच्छुक है।

(16) मामले के इस दृष्टिकोण में, मुझे नीचे दिए गए न्यायालयों के फरमानों और निर्णयों में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं मिलता है। इसलिए यह अपील विफल हो जाती है और तदनुसार खारिज कर दी जाती है।

एस.सी.के.

(अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय, वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके, और किसी अन्य उद्देश्य के लिया इसका उपयोग नहीं किया जा सकेगा। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।)

रवि अमितोज़, प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी